RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : गुरुवार 07 दिसंबर 2023 | वर्ष 05 | अंक 225 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

# दैनिक रोकठोक लेखनी ®

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

## राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी बाबा साहेब आंबेडकर को श्रद्धांजलि

**मुंबई,** महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस और अजित पवार ने संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आंबेडकर की पुण्यतिथि को 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है। बाबा साहेब की पुण्यतिथि के मौके पर नेताओं ने मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क में उनके स्मारक 'चैत्यभूमि' पर पुष्पांजलि अर्पित की।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के संस्थापक शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी 'चैत्यभूमि' पर पहुंचकर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। शरद पवार ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में आंबेडकर को समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ने के वास्ते सामाजिक क्रांति लाने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया।

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) ने कहा कि स्मारक पर बड़ी संख्या में अनुयायियों की मौजूदगी आंबेडकर के काम और उनकी विचारधारा का प्रमाण है। हर साल छह दिसंबर को राज्य भर से हजारों लोग चैत्यभूमि पर एकत्र होते हैं। बाबा साहेब आंबेडकर का निधन छह दिसंबर 1956 को हुआ था।

# शरद पवार, उद्धव ठाकरे और दिग्विजय सिंह नागपुर की एक रैली में दिखेंगे एक साथ

## 12 दिसंबर को होगा कार्यक्रम

**मुंबई।** राकांपा संस्थापक शरद पवार, शिवसेना (उद्धव गुट) प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह 12 दिसंबर को नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद गुट) की युवा संघर्ष यात्रा के समापन पर एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे।

राकांपा शरद पवार गुट के नेता एवं राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तीनों नेता नागपुर के जीरो माइल इलाके में एक रैली को संबोधित करेंगे। कर्जत जामखेड विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राकांपा विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में युवा संघर्ष यात्रा महाराष्ट्र में युवाओं के सामने आने वाले मुद्दों सहित विभिन्न मुद्दों को उजागर करने के लिए 24 अक्टूबर को पुणे से शुरू हुई थी। अब यह पैदल मार्च नागपुर से लगभग 120 किमी दूर है।

राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान 800 किमी से अधिक की दूरी तय करने के बाद इसका समापन नागपुर में होना है। उन्होंने कहा कि शरद पवार, ठाकरे और दिग्विजय सिंह के अलावा महाविकास अघाड़ी (एमवीए) के अन्य नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। बता दें कि राकांपा संस्थापक शरद पवार उसी दिन 83 वर्ष के हो जाएंगे। देशमुख ने विश्वास जताया है कि जब भी विधानसभा चुनाव होंगे एमवीए जीतेगा और राज्य में सत्ता में वापसी करेगा।

## 'किसी भी तरह की ढिलाई नहीं कर सकते स्वीकार'

### आग लगने की घटनाओं पर शिंदे सरकार को HC की कड़ी फटकार

**मुंबई,** बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अग्नि सुरक्षा नियमों को ताक पर रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई। उसने कहा कि हर दूसरे दिन मुंबई में आग लगने की कोई न कोई घटना होती है, जिसमें मासूम लोगों की जान चली जाती है।

**यह मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर**

मुख्य न्यायाधीश (सीजे) डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई को स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती दिख रही हैं। इस शहर में हर दूसरे दिन आग लगने की घटना होती है और लोगों की जान जाने की खबरें आती हैं।

**यह बिल्कुल सही नहीं**

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह अदालत का काम नहीं है कि वह सरकार को बताए कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सीजे उपाध्याय ने कड़े शब्दों में सरकार पर सवालों की बौछार करते हुए कहा, 'यह बिल्कुल सही नहीं है। क्या हम आपको (सरकार को) हर कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए यहां बैठे हैं? क्या यह हमारा काम है? यह सब यहां क्या हो रहा है?' पीठ ने हाल ही में दक्षिण मुंबई में एक चार मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने की घटना का भी जिक्र किया। इस हादसे में 82 वर्षीय एक महिला और उसके 60 वर्षीय बेटे की जान चली गई थी। उन्होंने कहा कि ये दो मौतें जिस तरह हुई है, क्या आप इस शहर के लोगों के लिए यही चाहते हो कि परिवार अपने प्रियजनों को खोते रहें? अतिरिक्त सरकारी वकील ज्योति चव्हाण ने अदालत को सूचित किया कि पिछले साल गठित एक विशेषज्ञ समिति ने फरवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट को विचार के लिए राज्य के शहरी विकास विभाग के समक्ष रखा गया है और विकास नियंत्रण एवं संवर्धन नियंत्रण (डीसीपीआर) 2034 में संशोधन के लिए कदम उठाए जाएंगे।

## मुंबई कांग्रेस ने दादर स्टेशन का नाम बदलने की मांग की, कहा- विधानसभा में लाया जाए प्रस्ताव

**मुंबई,** कांग्रेस की मुंबई इकाई ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि कर दिया जाए. दरअसल, चैत्यभूमि वह जगह है जहां भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर ने अंतिम सांसें ली थीं. 6 दिसंबर को डॉ. अंबेडकर की पुण्य तिथि को 'महापरिनिर्वाण दिवस' के रूप में मनाया जाता है. हर साल इस दिन राज्य भर से हजारों की संख्या में लोग चैत्यभूमि में जुटते हैं.

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड ने चैत्यभूमि पर डॉ. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार ने इससे पहले केंद्र से मांग की थी कि एलफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभादेवी कर दिया जाए. उसी तर्ज पर दादर रेलवे स्टेशन का नाम भी चैत्यभूमि रखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह डॉ. अंबेडकर के लाखों अनुयायियों द्वारा लंबे समय से की जा रही मांग है. बता दें कि 2018 में राज्य सरकार ने एलफिंस्टन रोड स्टेशन का नाम बदलकर प्रभादेवी कर दिया था. वर्षा गायकवाड ने कहा कि ओशिवारा में जब नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था तो इसका नाम राम मंदिर रखा गया था. अगर हम उस बारे में विचार करें तो फिर दादर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चैत्यभूमि करने की भीमसैनिकों की मांग बहुत पुरानी है. वर्षा ने कहा कि उनकी मांग कोई उग्र नहीं थी, लेकिन यदि दूसरी मांगें पूरी हो गईं, और लाखों अनुयायी कई वर्षों से दादर स्टेशन का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं. तो इसमें क्या दिक्कत है.

## शीतकालीन सत्र में शिंदे सरकार को घेरने की तैयारी,

**मुंबई,** महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र गुरुवार (7 दिसंबर) से नागपुर में शुरू हो रहा है। आम चुनाव और आगामी अन्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। मराठा और धनगर आरक्षण के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने होंगे। सत्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने राज्य सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। खबर है कि शीतकालीन सत्र के लिए शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी के सभी विधायकों को खास निर्देश दिए हैं। शीतकालीन सत्र में आदित्य ठाकरे हर दिन उपस्थित रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल करेंगे। वहीं, उद्धव ठाकरे 11 या 12 दिसंबर को खुद सदन में मौजूद रह सकते है। जबकि कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बनायीं है।

# संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

## जिंदा हैं क्षेत्रीय दल

मिजोरम में पांच साल पुराने क्षेत्रीय दल 'जोराम पीपुल्स मूवमेंट' (जेडपीएम) को जनादेश देकर 35 साल पुरानी राजनीतिक जुगलबंदी को तोड़ा गया है। यह एक नए क्षेत्रीय दल की नाटकीय जीत है। जेडपीएम के पक्ष में ऐसी लहर थी, जिसमें मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी पराजित हो गए। मिजो नेशनल फ्रंट जैसे ताकतवर दल का लगभग सूपड़ा साफ हो गया। भाजपा और कांग्रेस सरीखे राष्ट्रीय दलों के हिस्से क्रमशः 2 और 1 सीट ही आई। अब मुख्यमंत्री पद पर एक नया चेहरा होगा-लालदुहोमा। अभी तक सत्ता की बंदरबांट जोरमथांगा और ललथनहवला के बीच जारी रही थी। उनके जरिए भाजपा और कांग्रेस का वर्चस्व भी बना रहता था, लेकिन ताजा चुनाव में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षा प्रभारी रहे लालदुहोमा की नवजात पार्टी को स्पष्ट जनादेश मिला है, तो माना जा सकता है कि क्षेत्रीय दल अब भी जिंदा हैं। लालदुहोमा कांग्रेस के सांसद रहे हैं, लिहाजा उनका कुछ राजनीतिक झुकाव कांग्रेस की तरफ स्वाभाविक है, लेकिन यह जनादेश उन्होंने एमएनएफ, भाजपा और कांग्रेस सरीखी ताकतों से लडकर हासिल किया है। दरअसल राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस तरह भाजपा और कांग्रेस को जनादेश मिले हैं, उनके मद्देनजर व्याख्या की जा रही है कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व खतरे में है, क्योंकि जनादेश राष्ट्रीय दलों के पक्ष में दिए जा रहे हैं। मिजोरम देश के हाशिए पर स्थित ऐसा छोटा-सा राज्य है, जिसका पड़ोसी मणिपुर है। वहां के जातीय, विभाजक, हिंसक और हत्यारे टकरावों का प्रभाव मिजोरम में भी है। हजारों कुकी लोग विस्थापित होकर मिजोरम में आए हैं। म्यांमार के घुसपैठिए यहां भी आते हैं। बेशक पुराना उग्रवाद लगभग शांत है, लेकिन यह एक आत्मनिर्भर राज्य नहीं है। मिजोरम को नई दिल्ली में भाजपा या कांग्रेस की सत्ताओं का सहारा हर हाल में चाहिए।

उसके बावजूद वहां की जनता ने एक नवजात दल को समर्थन दिया है, तो यह भी लोकतंत्र की खूबसूरती है। बेशक कुछ ही राज्यों में क्षेत्रीय दल प्रासंगिक बचे हैं, अलबत्ता दिल्ली में उनका प्रभाव धुंधला रहा है। 1989 से 2014 के बीच क्षेत्रीय दलों का जलवा था, क्योंकि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा था। क्षेत्रीय दल देश की सत्ता के सूत्रधार बन गए थे। चूंकि 2014 में केंद्र में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके साथ ही क्षेत्रीय दलों के अंत की शुरूआत हो गई। हालांकि कुछ क्षेत्रीय दल 'प्रतीक-रूप' में ही मोदी सरकार में शामिल हैं। भाजपा ने क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर धकेलना शुरू किया है।

भाजपा उप्र और महाराष्ट्र में भी वर्चस्ववादी ताकत के रूप में स्थापित हो चुकी है, नतीजतन क्षेत्रीय दलों में उथल-पुथल मची है। 2014 के बाद से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के बीच दो तरह की राजनीतिक साझेदारियां चल रही हैं। आंध्रप्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस और ओडिशा में बीजद आज भी अपने-अपने राज्य में सत्तारूढ़ ताकत हैं। भाजपा के साथ उनकी खास किस्म की साझेदारी है। वे संसद में, खासकर राज्यसभा में, भाजपा को समर्थन देते हैं। बदले में भाजपा उन्हें परेशान नहीं करती। तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल द्रमुक का गठबंधन में वर्चस्व है। बिहार और महाराष्ट्र में संतुलन की स्थितियां हैं। चुनावों में राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों का सहारा लेना ही पड़ता है।

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

# मनसे की चेतावनी !

## नगर निगम विभाग के दफ्तर में छोड़े जाएंगे चूहे और कॉकरोच...

**मुंबईः** सांताक्रूज के कई हिस्से पिछले दो वर्षों से दूषित और अपर्याप्त जल आपूर्ति से पीड़ित हैं। इस समस्या के समाधान के लिए मुंबई नगर निगम के संबंधित विभाग कार्यालय में दो बार मार्च निकाला गया. हालांकि नगर पालिका ने अभी इस पर निर्णय नहीं लिया है। इसके चलते मनसे ने चेतावनी दी है कि नगर निगम विभाग कार्यालय में 10 हजार चूहे-चूहे छोड़े जाएंगे. पिछले दो वर्षों से कालीना विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 89 के निवासियों को लगातार दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और नागरिकों ने दो बार मनपा विभाग कार्यालय पर मार्च निकाला. इस बीच नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से कुछ ही दिनों में इस समस्या का समाधान करने का वादा किया. लेकिन, सात-आठ माह बाद भी इस इलाके में पानी की समस्या बरकरार है. इसलिए मनपा प्रशासन को दिया गया वादा याद दिलाने के लिए मनसे ने मनपा के एच. मनसे कार्यकताओं की ओर से कहा गया है कि पूर्वी डिविजन कार्यालय में 10 हजार चूहे-चूहे छोड़े जाएंगे. क्षेत्र के गादेवी, मिलिंद नगर, वाघरीवाड़ा, लालबहादुर शास्त्रीनगर, सुब्रमण्यम नगर, डिमेलो कंपाउंड और नवजीवन आदि के निवासी अपर्याप्त और दूषित जलापूर्ति के कारण हैरान हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी सवाल खड़ा हो गया है। पूर्व में दो बार नगर पालिका के डिविजनल कार्यालय पर मार्च निकाला जा चुका है। उस समय नगर पालिका की ओर से लिखित रूप से कहा गया था कि पानी की समस्या को संज्ञान में लेकर शीघ्र समाधान कराया जाएगा। हालांकि, मनसे शाखा अध्यक्ष संतोष उपरालकर ने आरोप लगाया कि सात से आठ महीने बाद भी नगर पालिका ने कोई कार्रवाई नहीं की है.

## नालासोपारा में देशी कट्टा लेकर घूम रहा बदमाश गिरफ्तार

**नालासोपारा :** मुंबई से सटे नालासोपारा पूर्व क्षेत्र में पुलिस ने एक 24 वर्षीय शख्स को एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ तुलिंज थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार, तुलिंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नालासोपारा पूर्व के ओसवाल नगरी क्षेत्र में अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल छापामार कार्रवाई करते हुए ओसवाल नगरी क्षेत्र से एक दुर्वेश दत्ताराम जुवले (24) नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दुर्वेश के पास से एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए, जिनकी कुल कीमत 10,400 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 325(1), (ब) 37 (1)/135 के तहत केस दर्ज किया है।

## १६ दिसंबर को धारावी से अडानी कार्यालय पर प्रचंड मोर्चा

**मुंबई :** धारावी पुनर्विकास परियोजना को स्पेशल प्रोजेक्ट घोषित करने के बाद भी धारावीकरों को केवल ३०० वर्ग फुट की जगह देने की साजिश सरकार ने की है। इतना ही नहीं, विकासक अडानी पर केवल सहूलियतों की बारिश इस सरकार ने की है। कोई भी आपत्ति और सूचना मंगाए बिना सरकार ने सीधे विकास की जिम्मेदारी दे दी है। खासकर इस स्थान का टीडीआर मुंबई में कहीं भी इस्तेमाल करने की सहूलियत अडानी को दिए जाने से अन्य विकासकों को पहली बार टीडीआर इस्तेमाल करना है, तो अडानी से अनुमति लेनी पड़ेगी। यह मामला यानी 'सारी मुंबई अडानी की' ऐसा है। इसी में सर्वे लटक गया है और पुनर्विकास को लेकर धारावीकरों को कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। इसलिए सरकार और अडानी से जवाब मांगने के लिए १६ दिसंबर को धारावी से अडानी कार्यालय पर प्रचंड मोर्चा निकाला जाएगा। इस तरह की घोषणा शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल की। उद्धव ठाकरे खुद मोर्चा का नेतृत्व करेंगे। शिवसेना के नरीमन प्वाइंट स्थित 'शिवालय' राज्य संपर्क कार्यालय के नूतनीकरण का उद्घाटन उद्धव ठाकरे के हाथों हुआ। इस दौरान पत्रकार परिषद में उन्होंने मुंबई समेत देश के विभिन्न मुद्दों को उठाया।

## माहिम पुलिस ने डोंगरी से लापता हुए नूरुलहक को उसके बच्चों से उनको मिलवाया

**माहिम :** डोंगरी के रहवासी नूरुलहक शाम ८ बजे से घर से लापता थे उनके घर वालो ने मिसिंग कंप्लेंट डोंगरी पुलिस थाने में की थी । देर रात माहिम पुलिस थाने के बीट मार्शल कांस्टेबल पवार और देवरे को बुजुर्ग व्यक्ति दिखा उनसे पूछताछ कि तो वह डोंगरी के है बता रहे थे उम्र दराज होने के कारण सही एड्रेस बताने में दिखत हो रही थी लेकिन मुंबई पुलिस ने बुजुर्ग व्यक्ती को पानी पिलाया और घर वालो से कुछ ही घंटे में मिलाया ।

मलिक नामक स्तानिक व्यक्ति ने इस घटना की रिकॉर्डिंग कि और फेसबुक पे डाली और उनके घर वालो तक वीडियो पहुचा और अपने पिता से मिलने में सफल रहे । घर वालो ने मुंबई पुलिस के कांस्टेबल पवार और देवरे का शुक्रिया अदा किया ।

## कमजोर हुई है कांग्रेस की पावर, बदलेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का समीकरण

**मुंबई :** तीन राज्यों में कांग्रेस की हार का असर कई राज्यों में पार्टी के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ने वाला है. दरअसल इसी साल कर्नाटक के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस बीजेपी-विरोधी गुट में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी हुई है. लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे अहम चुनावी राज्यों में हार ने न सिर्फ पार्टी की पोजीशन 'इंडिया' गठबंधन में कमजोर की है बल्कि महाविकास अघाड़ी के भीतर भी की है. कांग्रेस ने तेलंगाना में बहुमत के आस-पास ही सीटें हासिल की हैं यानी ये बहुमत की प्राप्ति है न कि प्रचंड चुनावी जीत. जैसी कि कांग्रेस ने कर्नाटक जैसे राज्य में हासिल की है. ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में भी पार्टी की बार्गेनिंग पावर यानी सीटों पर तोलम-मोल की क्षमता कमजोर हुई है. यह ध्यान रखने वाली बात है कि लोकसभा चुनाव के साथ ही अगले महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के अलावा एनसीपी और शिवसेना का उद्धव गुट शामिल है.

एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कर्नाटक चुनाव के बाद महाराष्ट्र में लगातार आगामी चुनावों के लिए ज्यादा सीटों को लेकर ताकत लगा रही थी. विशेष रूप से विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र के भीतर. लेकिन अब चुनावी हार के बाद कांग्रेस की यह मांग एनसीपी और उद्धव गुट की तरफ से ठुकराई भी जा सकती है.

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 07 दिसंबर 2023

# मुंबई शहर हल्के कोहरे में...
## हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार

**मुंबई :** मुंबई शहर मंगलवार सुबह हल्के कोहरे में लिपटा नजर आया। साथ ही शहर में हवा की गुणवत्ता 'मध्यम' श्रेणी में दर्ज की गई है। समीर ऐप के मुताबिक, कल सुबह १० बजे मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स १३६ था, जो दो-तीन दिनों से बरकरार है। साथ ही यह भी देखा गया कि पीएम १० धूल कणों की मात्रा अधिक थी। कुल मिलाकर बीते दो-तीन दिनों से मुंबई की हवा में मामूली सुधार नजर आ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार, बोरीवली, वर्ली और मुलुंड में वायु गुणवत्ता सूचकांक क्रमशः ९३, ९३ और ८९ था। इसके अनुसार यहां की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक दर्ज की गई है। इस बीच कोलाबा, शिवड़ी समेत शिवाजी नगर में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है। शिवाजी नगर का वायु गुणवत्ता सूचकांक २१७, शिवड़ी का २५० और कोलाबा का २५१ रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानदंडों के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक ०-५० के बीच अच्छा, ५१-१०० के बीच संतोषजनक, १०१-२०० के बीच मध्यम, २०१-३०० के बीच खराब, ३०१-४०० के बीच बहुत खराब और ४०० से ऊपर खतरनाक वायु गुणवत्ता मानी जाती है। मुंबई शहर और उपनगरों के लिए भारतीय मौसम विभाग के दैनिक पूर्वानुमान भविष्यवाणी में सुबह कोहरा था, जबकि दिन में ज्यादातर साफ आसमान दिखा। कुछ दिन पहले मुंबई में गुलाबी ठंड पड़ रही थी। हालांकि, मुंबई समेत पूरे राज्य में कई जगहों पर बेमौसम बारिश हुई, जो रुक गई। इससे प्रदूषण में कमी तो आई, लेकिन चक्रवात मिचांग के प्रभाव के कारण दो और चार दिसंबर के बीच मुंबई में न्यूनतम तापमान में वृद्धि हुई। आलम यह है कि दिसंबर के महीने में भी मुंबईकरों के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में मुंबई वासियों को ठंड का इंतजार है।

# मुंबई शहरी क्षेत्र में पानी की कटौती...
## मालाबार हिल जलाशय का आंतरिक निरीक्षण

**मुंबई:** मालाबार हिल जलाशय के पुनर्निर्माण के संबंध में निर्णय लेने के लिए नगर पालिका द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति गुरुवार, 7 दिसंबर को जलाशय का निरीक्षण करेगी। आय. आय. टी. पवई प्रोफेसर, स्थानीय विशेषज्ञ नागरिक। नगर निगम अधिकारियों की एक विशेषज्ञ समिति मालाबार हिल जलाशय में कप्पा नंबर 2 का आंतरिक निरीक्षण करेगी। इसलिए जलाशय के टैंक नंबर 2 को खाली करना होगा और इसके कारण शहर के कई हिस्सों में पानी की कटौती होगी और कुछ जगहों पर पानी की आपूर्ति बाधित करनी पड़ेगी।

पूरे दक्षिण मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाले मालाबार हिल जलाशय के पुनर्निर्माण का मुद्दा पिछले कुछ महीनों से गरमाया हुआ है। 136 साल पुराने इस जलाशय का निर्माण 1887 में हैंगिंग गार्डन यानी फि रोज शाह मेहता पार्क के नीचे किया गया था। लेकिन यदि इस जलाशय का पुनर्निर्माण किया गया तो 389 पेड़ प्रभावित होंगे। साथ ही पार्क को सात साल के लिए बंद करना पड़ेगा। इसलिए, निवासियों और पर्यावरणविदों ने इस पार्क के पुनर्निर्माण का विरोध किया है। इसलिए इस जलाशय के पुनर्निर्माण या मरम्मत के विकल्पों पर चर्चा शुरू हो गई है। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए पालक मंत्री और दक्षिण मुंबई के विधायक मंगलप्रभात लोढ़ा ने नागरिकों की एक बैठक बुलाई थी और नागरिकों की एक समिति बनाई थी, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर मनपा प्रशासन ने पिछले महीने एक समीक्षा समिति का गठन किया है. समिति में आईआईटी के निदेशक द्वारा नियुक्त तीन प्रोफेसर और नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति, जिसे अपना निर्णय देने के लिए एक महीने का समय दिया गया था, एक विशेषज्ञ समिति के माध्यम से गुरुवार, 7 दिसंबर को मालाबार हिल जलाशय में कप्पा नंबर 2 का आंतरिक निरीक्षण करेगी। इसलिए, जलाशय के डिब्बे नंबर 2 को खाली करना होगा। इससे शहर के कुछ हिस्सों में पानी कम हो जाएगा और कुछ हिस्सों में जलापूर्ति बाधित करनी पड़ेगी। विशेषज्ञ समिति गुरुवार 7 दिसंबर को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक इस 2 घंटे की अवधि के दौरान जलाशय का आंतरिक निरीक्षण करेगी। उसके लिए कप्पा खाली करने से मुंबई शहर में पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी. साथ ही कुछ जगहों पर पानी का दबाव कम रहेगा।

# डेंगू ने मचाया कोहराम...

**मुंबई :** हर साल डेंगू के मामले देखने को मिलते हैं। हर साल हजारों लोग डेंगू के शिकार होते हैं और सैकड़ों लोगों को इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस साल भी डेंगू ने देशभर में कोहराम मचाया हुआ है। इस साल देश सबसे अधिक डेंगू के मामलों और मौतों वाले शीर्ष २० देशों में शामिल हो गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्थान में पिछले पांच वर्षों की तुलना में इस साल अधिक मामले दर्ज किए गए। एक रिपोर्ट से पता चला है कि इस साल नवंबर २०२३ तक सबसे अधिक प्रभावित २० देशों में डेंगू बुखार के ५० लाख मामले दर्ज किए गए, जो २०२२ की तुलना में ३० प्रतिशत और २०१९ के आंकड़ों से १८ फीसदी अधिक हैं। इसमें यह भी पाया गया कि हिंदुस्थान सहित २० देशों में डेंगू से कम से कम पांच हजार ५०० लोग मारे गए, जो २०२२ से ३२ प्रतिशत अधिक और २०१९ की तुलना में ११ प्रतिशत अधिक है।

# सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र जैसल पार्क चौपाटी जेट्टी प्लेटफार्म स्थानांतरित करने की मांग

**भायंदर :** शहर में जल परिवहन सेवा शुरू करने की कवायद जोर-शोर से शुरू हो गई है, जिससे भविष्य में शहरवासियों को ट्रैफिक जाम से निजात मिलने की उम्मीद है। पिछले दिनों अपने निरीक्षण दौरे के दौरान मनपा आयुक्त एवं प्रशासक संजय काटकर से इस प्रोजेक्ट से संबंधित निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध किया गया था। इस जल परिवहन सेवा में सबसे बड़ा पेंच अब जैसल पार्क चौपाटी पर इस सेवा के लिए बनाए जाने वाले जेट्टी प्लेटफार्म को लेकर फंस गया है। अब इसे स्थानांतरित करने की मांग उठ रही है। इसके लिए कई संस्थाओं ने सीएम सहित अन्य विभागों को पत्र लिखा है।

प्रस्तावित नई विकास नियंत्रण नियमावली (डीपी प्लान) में जैसल पार्क चौपाटी (आरक्षण क्रमांक ८१) को जल परिवहन स्टेशन (जेट्टी) के रूप में आरक्षित किया गया है, जिसका न सिर्फ स्थानीय नागरिकों, अपितु तमाम जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों तथा सामाजिक संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में जीवदया एवं तमाम सामाजिक कार्यों को अंजाम देने वाली संस्था जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव एवं मीरा-भायंदर महानगरपालिका के आयुक्त एवं प्रशासक संजय काटकर को पत्र लिखकर सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजनों के प्रमुख केंद्र जैसल पार्क चौपाटी से इस प्रस्तावित जल परिवहन सेवा के स्टेशन को कुछ और दूरी पर स्थानांतरित करने की मांग की है।

जैसल पार्क चौपाटी कल्याण समिति के महासचिव डॉ नरेंद्र गुप्ता ने इस बारे में बताया कि हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जैसल पार्क चौपाटी न सिर्फ स्थानीय नागरिकों, अपितु समूचे मीरा-भायंदर के लोगों के लिए एकमात्र जीवनदायक स्थल है। जहां मीरा -भायंदर के नागरिक, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग आदि सुबह-शाम खाड़ी के किनारे स्वच्छ व खुली हवा में टहलने के लिए आते हैं। यहीं पर बच्चों के खेलने के लिए मैदान हैं। यहीं पर अनेक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। सरल शब्दों में जैसल पार्क चौपाटी एक ऐसा स्थल है, जहां पर यहां के लोगों की जिंदगी सांस लेती है। जिसे यहां के लोग किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते।

# 'स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार OBC के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं,' राज्यसभा में सरकार ने कहा

**नई दिल्ली :** केंद्र ने बुधवार को राज्यसभा को सूचित किया कि स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ओबीसी को संविधान के अनुच्छेद 243 डी के तहत एक तिहाई आरक्षण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हालांकि, 21 राज्य सरकारों ने आरक्षण को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। सदस्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में जनसंख्या के अनुसार ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।''

**'स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण'**

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण है। पाटिल ने कहा, इस कोटा के तहत ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समायोजित करने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य सरकारों को ओबीसी के लिए आरक्षण देने का अधिकार है। केंद्रीय मंत्री ने एक अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, ''इस विषय पर राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेना चाहिए।'' उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटा मुद्दे के कारण महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुभवजन्य आंकड़ों के बिना आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण के बारे में पाटिल ने कहा कि केंद्र ने निर्वाचित महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें उन्हें छह महीने का प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है।

# बंद घरों को अपना शिकार बनाते थे, गिरोह को पुलिस ने किया गिरफ्तार

**नई मुंबई :** नई मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो बंद घरों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस द्वारा की गई जांच में इस मामले के आरोपी पर कई पुलिस स्टेशन में 12 मामले दर्ज है। इसी तरह एक आरोपी पर 14 मामले, वहीं दूसरे आरोपी पर 9, तीसरे आरोपी पर 7 और वहीं चौथे आरोपी पर 1 मामला पहले से दर्ज हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी अनुसार सीबीडी पुलिस स्टेशन की हद के एक घर में अज्ञात चोरों ने दिनदहाड़े घुसकर 8 लाख 32 हजार रुपए का सामान चोरी किये थे। इस मामले को पुलिस ने दर्ज कर सीबीडी पुलिस स्टेशन की क्राइम डिटेक्शन टीम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उक्त अज्ञात आरोपी की तलाश में दिन-रात अथक मेहनत की और 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की जांच करके आरोपी की पहचान की। इसके बाद इन आरोपियों को नाशिक, शिर्डी, सातारा, कोल्हापुर, पुणे व पालघर इलाके में तलाश कर महाराष्ट्र- गुजरात बॉर्डर पर धर दबोचा। पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने चार चोरी की घटनाओं को अंजाम देने का बात कबूल की है।

# इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ज्वैलरी कारोबारी के घर मारा छापा

## 18 लाख कैश लेकर हुए चंपत...यूं हुआ खुलासा

**मुंबईः** 10 साल पहले आई बॉलीवुड की फिल्म 'स्पेशल 26' की तर्ज पर मुंबई में एक घटना सामने आई हैं। इसमें खुद को आयकर (कर) ऑफिसर्स बताकर आठ जालसाजों के एक गैंग ने पहले एक ज्वैलरी कारोबारी के घर पर छापा मारा। इसके बाद शादी के लिए रखे गए 18 लाख रुपयों को सीज करके रफूचक्कर हो गए। इस घटना ने बॉलीवुड के फिल्म स्पेशल 26 की कहानी की याद दिला दी है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालकर पुलिस ने कुछ संदिग्धों को अरेस्ट किया है।

**छापेमारी के दौरान जमा करा लिए फोन**

ज्वैलरी कारोबारी की बेटी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि राजकुमार उनके बेटे का दोस्त था। 26 नवंबर को गिरोह ने सायन में चिदंबरम रोड के फ्लैट पर आईटी विभाग का ऑफिसर बताकर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने अपने फर्जी आईडी कार्ड दिखाए। छापेमारी के दौरान परिवार के सभी सदस्यों के मोबाइल के ले लिए और फ्लैट को अंदर से बंद कर लिया। इसके बाद छापेमारी को अंजाम दिया। छापेमारी में एक अलमारी से 18 लाख रुपये मिले। जो परिवार ने एक बेटी की शादी के लिए बचाकर रखे थे। छापेमारी के बाद जब ज्वैलरी कारोबारी को शेक हुआ तो उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट अब्दुल फैज से संपर्क किया। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

हमने उस कार के रिवर्स सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जिसमें आरोपी आए थे और पाया कि वह मानखुर्द से आई थी, जहां नंबर प्लेटें बदली गई थीं। हमें इसका असली नंबर मिल गया, जो मंगले की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड था। हमने मंगले को मानखुर्द से उठाया, जहां वह महाराष्ट्र नगर में केक की दुकान चलाता है। तकनीकी मदद से हमने उनमें से आठ को एक के बाद एक गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत कदम, डीसीपी (जोन 4) मुंबई पुलिस

**एक संदिग्ध का परिवार ने कनेक्शन**

सायन पुलिस स्टेशन की वरिष्ठ निरीक्षक मनीषा शिर्के ने कहा कि छापेमारी के दौरान इन्होंने काफी कुछ तरीका आय अधिकारियों जैसा अपनाया। उन्होंने परिवार को बताया कि उन्हें उनके पास बड़ी मात्रा में नकदी जमा होने की सूचना मिली है। परिवार से उसे बाहर निकालने के लिए कहा। पुलिस द्वारा पकड़े गए संदिग्धों में राजकुमार गुज्जर (38) की ज्वैलरी कारोबारी के पोते से दोस्त है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस घटना का मुख्य सुशांत लोहार जो आईटी विभाग में था। उसने गिरोह के सदस्यों को कहा था कि छापेमारी करें। इसके लिए उन्हें 10 फीसदी कमीशन मिलेगा। कमीशन की लालच में इन्होंने छापेमारी के लिए राम कुबेर पटवा को चुना, क्यों पटवा को एक प्रॉपर्टी डील में 10 करोड़ रुपये कैश में मिले थे। आयकर अधिकारी बनकर छापेमारी करने वाले सदस्यों ने कैश को जब्त करने के बाद फर्जी पंचनामा भी बना दिया। इसके बाद परिवार को आईटी की नोटिस का इंतजार करने को कहा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सुशांत लोहार ने अभय कासले को छापे के लिए भर्ती किया था।

**18 लाख की बरामदगी बाकी**

पुलिस ने राजकुमार गुज्जर के अलावा संतोष पटले, राजाराम मांगले , अमरदीप सोनावणे, और शरद एकावड़े को गिरफ्तार किया है, हालांकि पुलिस अभी तक इन द्वारा जब्त किए गए 18 लाख रुपये की रकम बरामद नहीं कर पाई है। पुलिस ने छापेमारी में इस्तेमाल की गई एक कार और एक फर्जी पहचान पत्र जब्त कर लिया है। पुलिस छापेमारी में शामिल युवकों पुलिस की वर्दी पहने हुए दो तस्वीरें मिलीं।

# हाईवे की कंक्रीटिंग में देरी...

## केंद्रीय मंत्री के आश्वासन के एक माह बाद भी काम शुरू नहीं हुआ

**वसईः** मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग को गड्ढामुक्त और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए 121 किमी तक व्हाइट टॉपिंग की गई। द्रीय मंत्री नितिन गडकरी की एक माह में काम पूरा करने की घोषणा खोखली निकली है। इस घोषणा को एक महीना बीत गया, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ. हालांकि, हाईवे अथॉरिटी ने जल्द ही काम शुरू करने की बात कहकर इतिश्री कर ली है। बई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग वसई पूर्व से होकर गुजरता है। यह मुंबई, ठाणे, वसई विरार, पालघर, सूरत सहित गुजरात के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। इस हाईवे पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन चलते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस नेशनल हाईवे पर गड्ढों की समस्या पैदा हो गई है और हाईवे बेहद खतरनाक हो गया है. लगातार हादसे की घटनाएं सामने आ रही हैं. उसके समाधान के तौर पर अब हाईवे पर व्हाइट टॉपिंग की जाएगी। करीब 121 किलोमीटर हाईवे की व्हाइट टॉपिंग की जाएगी और सड़क पर व्हाइट टॉपिंग के छोटे-छोटे पैनल बनाए जाएंगे. लेकिन यह काम शुरू नहीं हुआ.

3 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वसई जनता बैंक के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के लिए विरार में थे। उस वक्त उन्होंने माना था कि वसई विरार की राह कठिन है. उन्होंने यह भी कहा था कि मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर होने वाले हादसों की वजह से उन्होंने इस हाईवे का नाम 'डेथ ट्रैप' रखा है. इसलिए उन्होंने घोषणा की थी कि अगले एक महीने में 121 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाईवे का सीमेंट कंक्रीट का काम शुरू किया जाएगा. इस घोषणा का लोगों ने तालियों से स्वागत किया क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने खुद इस काम के लिए तत्परता दिखाई. लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक हाईवे का काम शुरू नहीं हो सका है. लिहाजा, नागरिक पूछने लगे हैं कि क्या मंत्री की काम की घोषणा सिर्फ हवा-हवाई थी.

# राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि

**मुंबई :** राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र राज्य दूसरे स्थान पर है, यह चौंकानेवाली जानकारी राष्ट्रीय अपराध पंजीकरण विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट से सामने आई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में मुंबई और पुणे शहरों में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं और राज्य के गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस का होमटाउन नागपुर शहर तीसरे स्थान पर है। राज्य सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों की

सुरक्षा को प्राथमिकता देने का दावा किया था। सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा और अपराध को कम करने के लिए विशेष प्रयास करने का दावा किया है। पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र देश में तीसरे स्थान पर था, जबकि इस साल की रिपोर्ट में राज्य दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले (६५,७४३) हैं, जबकि महाराष्ट्र में (४५,३३१) मामले हैं। राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा मामले (४५,०५८) हैं। देश में ३१ हजार ५१६ यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। इनमें मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान (५३,३९९) दूसरे, उत्तर प्रदेश (३,६९०) तिसरे और महाराष्ट्र (२,९०४) चौथे स्थान पर है। देश में १ हजार १७ नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न हुआ है और सबसे ज्यादा लड़कियों का यौन उत्पीड़न उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हुआ है। राज्य में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले मुंबई में हैं। ३७० महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया है, इसके बाद पुणे में ३०७ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और तीसरे स्थान पर नागपुर शहर है, जहां २५१ महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है।

# मांड्या में हुआ कन्या भ्रूण हत्या गिरोह का भंडाफोड़, कर्नाटक सरकार ने मेडिकल स्कैनिंग केंद्रों पर शुरू की कार्रवाई

**कर्नाटक :** मांड्या जिले के एक दूरदराज के गांव में एक गुड़ फैक्ट्री में स्थापित मैक्सिफट सर्जिकल सुविधा में बड़े पैमाने पर कन्या भ्रूण हत्या करने वाले गिरोह का पदार्फाश होने के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को मेडिकल स्कैनिंग केंद्रों पर कार्रवाई शुरू कर दी। छापेमारी मांड्या जिला परिवार कल्याण अधिकारी वेंकटस्वामी और पांडवपुरा उप-मंडल सहायक आयुक्त नंदीश द्वारा की गई। उन्होंने उन स्कैनिंग केंद्रों को सील कर दिया जो सरकारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते थे और अपने रिकॉर्ड अप-टू-डेट नहीं रखते थे। पुलिस ने हाल ही में डॉक्टरों, नर्सों और एजेंटों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया

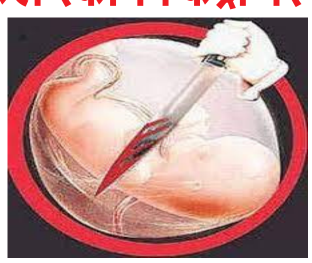

था, जिन्होंने कथित तौर पर 900 से अधिक कन्या भ्रूण हत्याओं को अंजाम दिया था।

पुलिस के मुताबिक, गिरोह गर्भवती महिलाओं से संपर्क करता था और उन्हें लिंग परीक्षण कराने के लिए राजी करता था, जिसके लिए वे 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच लेते थे। पुलिस ने कहा कि वे गुड़ फैक्ट्री में परीक्षण करते थे जहां सभी आवश्यक उपकरण रखे जाते थे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर परीक्षण में लड़की दिखती है, तो वे उन महिलाओं से पूछेंगे कि क्या वे इसका गर्भपात कराना चाहती हैं। एक बार जब महिलाएं सहमत हो गईं, तो टीम काम करने के लिए लगभग 50,000 रुपये चार्ज करेगी। गिरोह ने कम से कम 900 कन्या भ्रूण हत्याएं कीं। इस बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या मामले में सीआईडी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बेलगावी जिला मुख्यालय शहर में संवाददाताओं से कहा, रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

# नए साल में गड्ढामुक्त यात्रा की गारंटी...

**ठाणे :** ठाणेकरों को सड़कों पर यात्रा के दौरान गड्ढों को पार कर गुजरना पड़ता था। सड़कों के दोनों चरणों का काम ८५ प्रतिशत पूरा हो चुका है और ३१ दिसंबर तक इन कार्यों को पूरा करके मनपा ने नए साल में गड्ढामुक्त यात्रा की गारंटी दी है। अपनी दी गई डेडलाइन को पूर्ण करने में ठाणे मनपा सफल होती है या नहीं यह तो वक्त बताएगा। लेकिन मौजूदा समय में जनता परेशान है और ठाणे गड्ढामुक्त कब होगा, यह सवाल जनता पूछ रही है। बता दें कि पिछले वर्ष ३ दिसंबर २०२२ के दिन ठाणे मनपा द्वारा मुख्यमंत्री का बदलता ठाणे उपक्रम हाथ में लिया गया था।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं.4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर ४ , मदीना मेंशन, ८९ ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई ४०००१६ , महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 व्हाट्सप्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com